

सोनीपत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिति का एक अध्ययन

ज्योति रानी

शोधार्थी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल
बोहर-124021, रोहतक (हरियाणा)

(डॉ.) सुनीता यादव

शोध-निर्देशिका, प्रोफेसर भूगोल, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
अस्थल बोहर-124021, रोहतक (हरियाणा)

शोध सार :

सोनीपत भारत के हरियाणा राज्य का एक जिला है। इसे रोहतक जिले से अलग करके 22 दिसंबर 1972 को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया था। इस जिले का ऐतिहासिक महत्व है और यह सदियों से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, खासकर महाभारत के समय के दौरान। आज यह अपने आधुनिक उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और समृद्ध कृषि भूमि के लिए जाना जाता है। 22 दिसंबर 1972 को एक अलग जिले के रूप में स्थापित होने से पहले, सोनीपत भारतीय राज्य हरियाणा के बड़े रोहतक जिले का एक हिस्सा था। ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र की पृष्ठभूमि समृद्ध और प्राचीन है, जो अक्सर भारतीय महाकाव्य, महाभारत की पौराणिक घटनाओं से जुड़ी होती है। लोककथाओं के अनुसार, सोनीपत की स्थापना महाभारत के समय में पांच पांडव भाइयों द्वारा स्वर्णप्रस्थ के रूप में की गई थी।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश की 65% से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विकास ग्रामीण विकास पर निर्भर करता है। मजबूत बुनियादी ढाँचा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रवासन की दर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मुख्य रूप से सड़क और परिवहन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली और ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास, तथा संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे घटकों में विभाजित किया जा सकता है। सरकार ने ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), जल जीवन मिशन (JJM), सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन (SBM), भारतनेट परियोजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं।

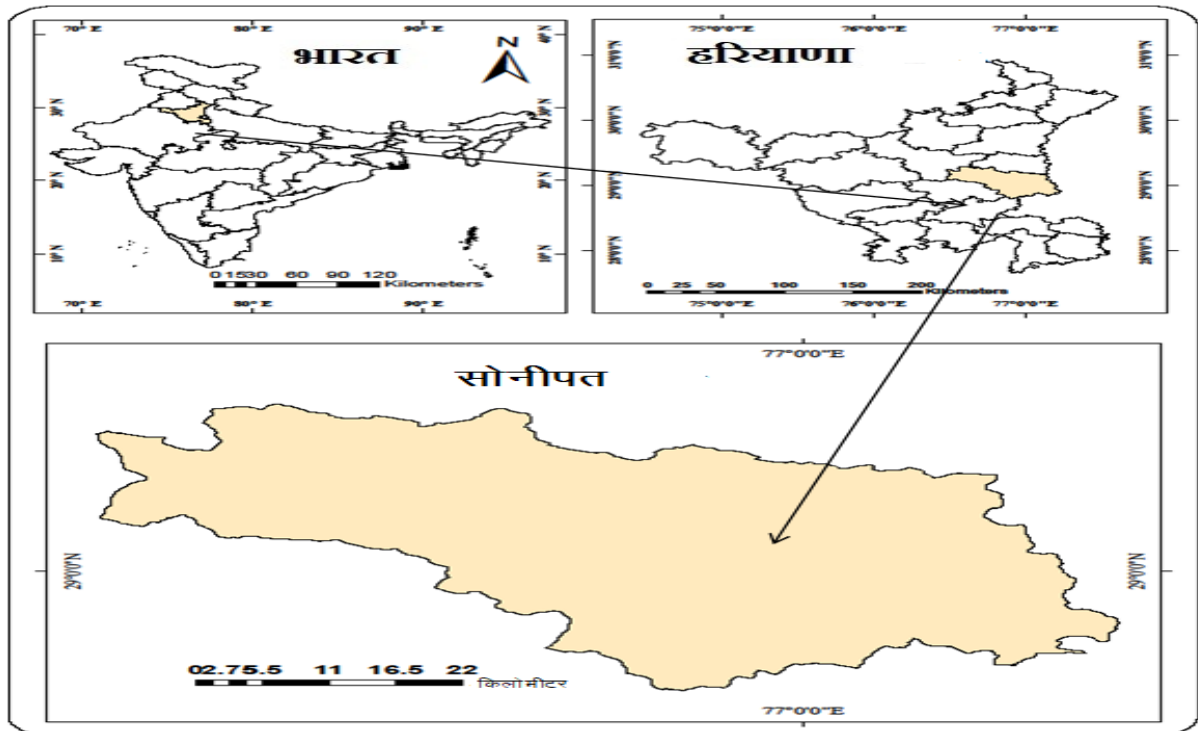
मुख्य शब्द : शैक्षणिक संस्थान, हरित क्रांति, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण कौशल विकास, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कृषि एवं सिंचाई, रोजगार सृजन।

भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार :

पृथ्वी पर किसी भी स्थान की अवस्थिति का ज्ञान हमें भूगोल विषय ही उपलब्ध कराता है। समस्त पृथ्वी काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं में विभाजित है। इन्हीं रेखाओं की सहायता से पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष की अवस्थिति और समय का बोध होता है। अक्षांश रेखाएं हमें पृथ्वी पर किसी क्षेत्र विशेष की अवस्थिति का ज्ञान कराती हैं तथा देशांतर रेखाएं हमें उस क्षेत्र विशेष के समय का बोध कराती हैं। पृथ्वी पर विभिन्न देशों, राज्यों, जिलों, गाँवों की अपनी-अपनी एक निश्चित भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार होता है। हरियाणा राज्य का सोनीपत जिला भी अपनी भौगोलिक स्थिति और विस्तार रखता है। सोनीपत जिला प्रायः समतल, मैदानी भाग में अवस्थित है जो हरियाणा प्रांत के उत्तरी-पूर्वी मध्य भाग में $28^{\circ}48'30''$ उत्तरी अक्षांश से $29^{\circ}17'54''$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $76^{\circ}21'31''$ पूर्वी देशांतर से $77^{\circ}13'40''$ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। सोनीपत जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 235.194 मीटर है। सोनीपत के उत्तर में पानीपत जिला पश्चिम में रोहतक व जीन्द जिला, दक्षिण में झज्जर तथा देश की राजधानी नई दिल्ली तथा पूर्व दिशा में यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा का निर्धारण करती है। आयतनुमा आकृति में विस्तृत जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2260 वर्ग किलोमीटर (870 वर्ग मील) है। सोनीपत जिले का मुख्यालय शहर के पश्चिमी भाग में है। यह दिल्ली से अमृतसर को जाने वाली लाइन पर अवस्थित है। जी.टी. रोड शेरशाह सूरी मार्ग शहर के पूर्वी किनारे से निकलता है। सोनीपत जिला भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा प्रदेश के उत्तरी-पूर्वी-मध्य भाग में मैदानी प्रदेश के रूप में स्थित है। मोटे तौर पर सोनीपत जिला हरियाणा-पंजाब मैदान का ही एक भाग है। अधिकतर जिले में महीन दोमट मृदा है। कुछ क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी भी है। प्रदेश में दक्षिण और पूर्व की ओर एक क्रमिक ढलान है। यमुना नदी के किनारे पर खादर मैदान : यह जिले के पूर्वी हिस्से में बहती हुई यमुना नदी के साथ-साथ संकरा बाढ़ का मैदान है। जिसकी चौड़ाई लगभग 3 से 6 किलोमीटर है। नदी के प्रवाह के साथ-साथ इसका निर्माण होता जाता है। खादर मृदा का मैदान 20 से 30 फीट नीचे वाला मैदान है। जो ऊपर के मैदान से सटा हुआ है।

अपलैंड का मैदान : इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सोनीपत तहसील का क्षेत्र है, जो खादर के पश्चिम में विस्तृत है, यह उपजाऊ मैदान कृषि भूमि से परिपूर्ण है। यह मैदान पुराने जलौढ़ से निर्मित है। यह क्षेत्र सिंचाई के अभाव में अत्यधिक उत्पादन से वंचित रह जाता है। इस क्षेत्र में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा कपास, गन्ने, बागवानी पौधों, सब्जियों और फूलों की खेती की जाती है। इस मैदान में गोहाना तहसील के रूप में विस्तार सोनीपत जिले के सुदूर पश्चिम तक है।

मानचित्र : अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति



स्रोत: शोधार्थी द्वारा क्यूजीआईएस की सहायता से निर्मित

जनसंख्या और जनसांख्यिकी

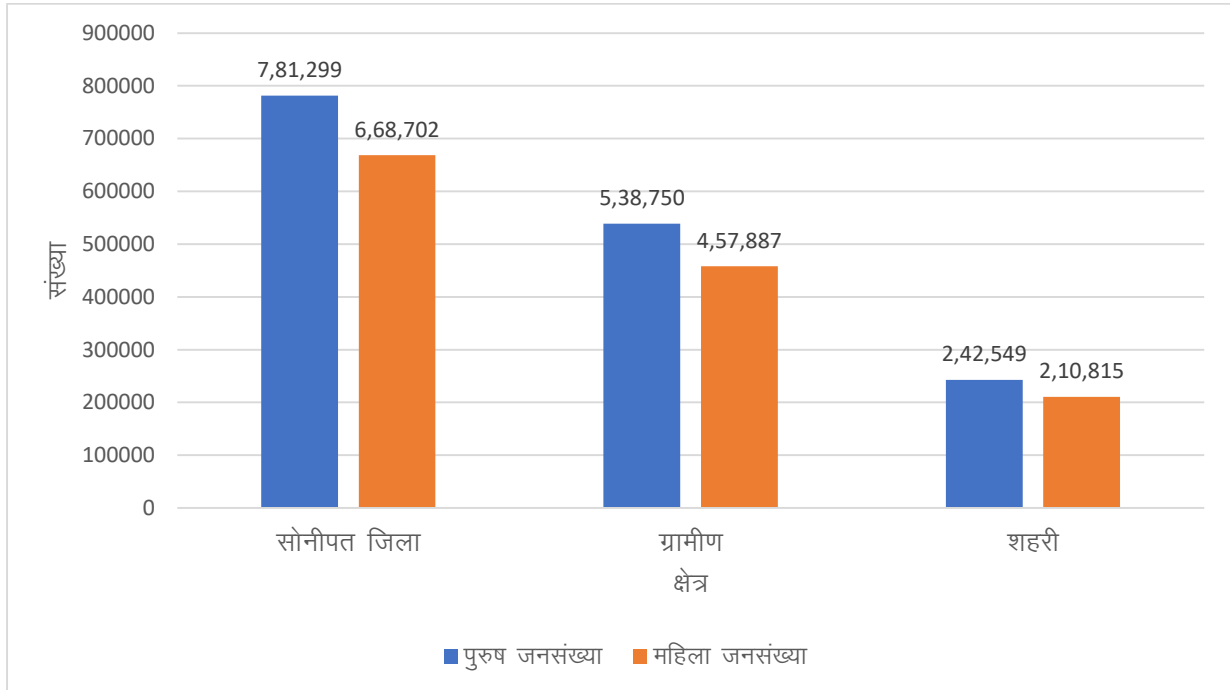
सोनीपत जिला हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 14,50,001 थी। इस जनसंख्या में 7,81,299 पुरुष और 6,68,702 महिलाएँ शामिल थीं। जिले में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच एक स्पष्ट अंतर देखा गया, जिसमें 68.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जबकि 31.27% लोग शहरी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सोनीपत में शहरीकरण धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। जिले का जनसंख्या घनत्व 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा के औसत से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जिससे भूमि और संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।

तालिका 1: सोनीपत जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या डेटा

क्षेत्र	कुल जनसंख्या	पुरुष जनसंख्या	महिला जनसंख्या	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
सोनीपत जिला	14,50,001	7,81,299	6,68,702	31.27
ग्रामीण	9,96,637	5,38,750	4,57,887	-
शहरी	4,53,364	2,42,549	2,10,815	100

स्रोत: जनगणना 2011, भारत सरकार।

आरेख 1: सोनीपत जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या डेटा



स्रोत: तालिका 1 पर आधारित

तालिका में सोनीपत जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इस तालिका में जिले की कुल जनसंख्या 14,50,001 दर्ज की गई है, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,81,299 और महिलाओं की संख्या 6,68,702 है। जनसंख्या को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 9,96,637 है, जिसमें 5,38,750 पुरुष और 4,57,887 महिलाएँ शामिल हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4,53,364 है, जिसमें 2,42,549 पुरुष और 2,10,815 महिलाएँ शामिल हैं। तालिका में जिले की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.27% दिखाया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र का प्रतिशत स्वाभाविक रूप से 100% है, क्योंकि इसमें केवल शहरी आबादी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए शहरी जनसंख्या प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। यह आंकड़े जिले में शहरीकरण की स्थिति को दर्शाते हैं और प्रशासनिक योजना एवं विकास कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

साक्षरता दर

शिक्षा के मामले में, जिले की कुल साक्षरता दर 79.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और हरियाणा में भी इसे एक अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है। पुरुषों की साक्षरता दर 87.2% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 69.8% है। यह बड़ा अंतर लैंगिक असमानता को दर्शाता है, जो महिलाओं की शिक्षा की कम प्राथमिकता और सामाजिक बाधाओं की ओर इशारा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 77.4% है, जो अपेक्षाकृत कम है, जबकि शहरी

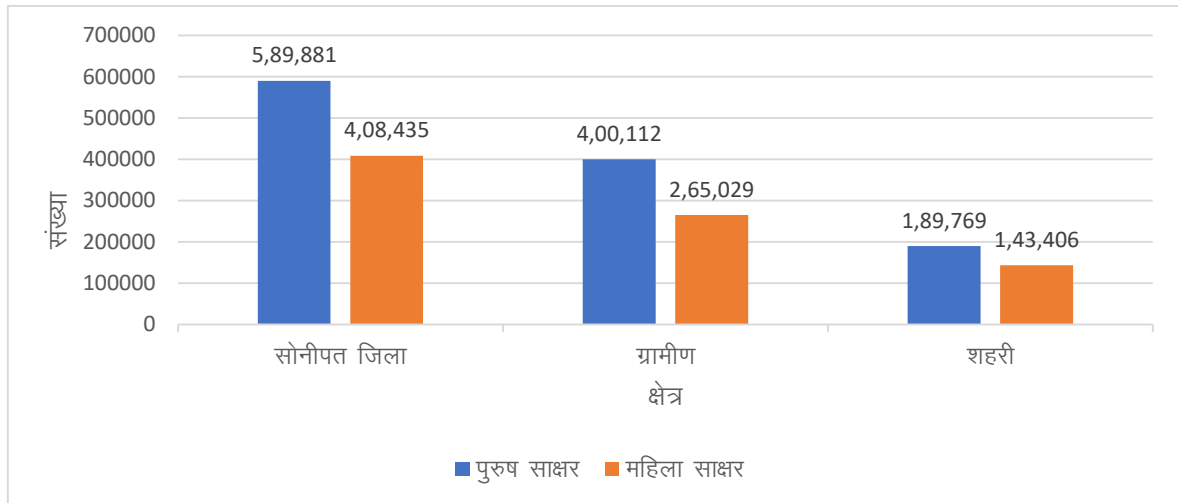
क्षेत्रों में यह 83.4% है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊँचा होने का कारण बेहतर विद्यालय, शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता और माता-पिता की उच्च शिक्षा प्राथमिकता हो सकती है।

तालिका 2: साक्षरता दर

क्षेत्र	कुल जनसंख्या	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	महिला साक्षर	साक्षरता दर (%)	पुरुष साक्षरता दर (%)	महिला साक्षरता दर (%)
सोनीपत जिला	14,50,001	9,98,316	5,89,881	4,08,435	79.1	87.2	69.8
ग्रामीण	9,96,637	6,65,141	4,00,112	2,65,029	77.4	85.3	67.2
शहरी	4,53,364	3,33,175	1,89,769	1,43,406	83.4	91.2	74.5

स्रोत: जनगणना 2011, भारत सरकार।

आरेख 2: साक्षरता दर



स्रोत: तालिका 2 पर आधारित

तालिका में सोनीपत जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। जिले की कुल जनसंख्या 14,50,001 है, जिसमें 9,98,316 लोग साक्षर हैं। पुरुषों की साक्षर जनसंख्या 5,89,881 और महिलाओं की 4,08,435 है। जिले का कुल साक्षरता दर 79.1% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 87.2% और महिलाओं की 69.8% दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 9,96,637 है, जिसमें 6,65,141 लोग

साक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 85.3% और महिलाओं की 67.2% है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है।

लिंगानुपात

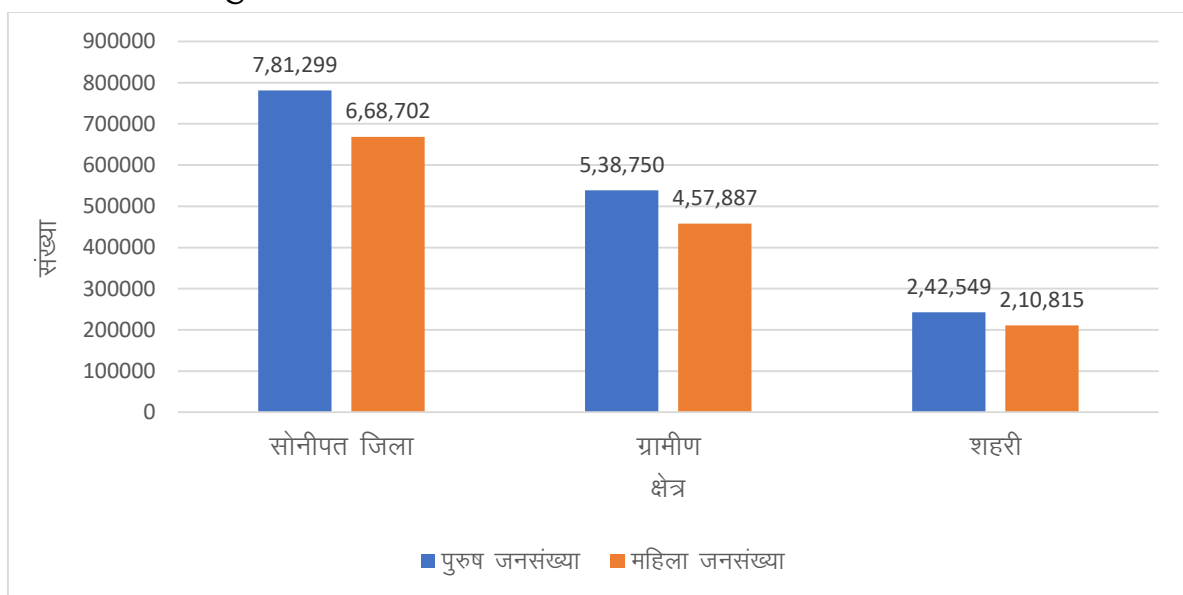
सोनीपत जिले में कुल लिंगानुपात 856 है, जो हरियाणा राज्य के औसत से थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी संतुलन में कमी दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 850 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 869 है। यह इंगित करता है कि शहरों में महिलाओं की संख्या की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी बेहतर है, जिसका कारण बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक जागरूकता हो सकती हैं। हालांकि, 0-6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है, जो केवल 798 है। यह इस बात का संकेत है कि जिले में कन्या भ्रूण हत्या या लड़कियों के जन्म को कम प्राथमिकता देने जैसी सामाजिक समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं।

तालिका 3: लिंग अनुपात

क्षेत्र	कुल जनसंख्या	पुरुष जनसंख्या	महिला जनसंख्या	लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएँ)
सोनीपत जिला	14,50,001	7,81,299	6,68,702	856
ग्रामीण	9,96,637	5,38,750	4,57,887	850
शहरी	4,53,364	2,42,549	2,10,815	869

स्रोत: जनगणना 2011, भारत सरकार।

आरेख 3: लिंग अनुपात



स्रोत: तालिका 3 पर आधारित

तालिका में सोनीपत जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। जिले की कुल जनसंख्या 14,50,001 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,81,299 और महिलाओं की संख्या 6,68,702 दर्ज की गई है। जिले का कुल लिंग अनुपात 856 है, अर्थात् प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 856 महिलाएँ हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिंग अनुपात की तुलना करने पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 9,96,637 दर्ज की गई है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,38,750 और महिलाओं की संख्या 4,57,887 है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात 850 है, जो जिले के औसत से भी कम है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4,53,364 है, जिसमें 2,42,549 पुरुष और 2,10,815 महिलाएँ शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात 869 है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिले में समग्र रूप से महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह असमानता अधिक देखी गई है। यह लिंग अनुपात सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को प्रतिबिंबित करता है और महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, तथा जन्म और मृत्यु दर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को इंगित करता है। यह डेटा नीति निर्माण और सामाजिक जागरूकता अभियानों के लिए उपयोगी हो सकता है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिति

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश की 65% से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विकास ग्रामीण विकास पर निर्भर करता है। मजबूत बुनियादी ढाँचा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रवासन की दर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मुख्य रूप से सड़क और परिवहन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली और ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास, तथा संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे घटकों में विभाजित किया जा सकता है। सरकार ने ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), जल जीवन मिशन (JLM), सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन (SBM), भारतनेट परियोजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं।

सड़क और परिवहन

सड़क और परिवहन प्रणाली ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के विस्तार में सहायक होती है। एक सुविकसित सड़क नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान होती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित होती है। इसी कारण, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से 7 लाख किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है, जिससे लाखों गाँवों को मुख्य राजमार्गों और

शहरों से जोड़ा गया है। PMGSY के तहत बनाए गए सड़क नेटवर्क ने ग्रामीण समुदायों को शहरों के साथ एकीकृत करने, कृषि बाजारों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करने, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, भारतमाला परियोजना और राज्य राजमार्ग विकास योजनाओं के तहत नई सड़कें और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण परिवहन नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

जल आपूर्ति और स्वच्छता की स्थिति किसी भी अन्य बुनियादी सुविधा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि कृषि उत्पादन, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास का भी आधार बनती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ जल संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई और घरेलू उपयोग में जाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी स्वच्छ जल की उपलब्धता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। गंदा और दूषित पानी पीने से जलजनित बीमारियाँ (जैसे डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा) फैलती हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) जैसी योजनाएँ शुरू की हैं, ताकि हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। जल जीवन मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब तक 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है, जो इस योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा, सरकार भूजल पुनःभरण, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर भी जोर दे रही है, ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके।

शिक्षा और कौशल विकास

शिक्षा और कौशल विकास किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। शिक्षा केवल साक्षरता दर बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार भी है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में शिक्षा का बुनियादी ढाँचा अब भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें स्कूलों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता, डिजिटल संसाधनों की सीमाएँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों का अभाव शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate) भी अधिक है, जो कि शिक्षा तक सीमित पहुँच और आर्थिक अस्थिरता के कारण होती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) जैसी योजनाएँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है।

सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को बढ़ाने और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख पहल है। इसके माध्यम से सरकार ने बुनियादी शिक्षा, विद्यालय निर्माण और छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा दिया है, ताकि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। इसके अतिरिक्त, मिड-डे मील योजना को विशेष रूप से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया गया, ताकि बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार किया जा सके और उनकी स्कूल उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। इस योजना से लाखों गरीब परिवारों को लाभ हुआ है, क्योंकि भोजन की गारंटी के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। केवल शिक्षा प्रदान करना पर्याप्त नहीं है; इसे रोजगार के अवसरों से जोड़ना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। इस योजना का लक्ष्य कृषि, लघु उद्योग, तकनीकी कौशल, डिजिटल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। हालाँकि, ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को अब भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, क्योंकि कई सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि कई गाँवों में इंटरनेट और स्मार्ट शिक्षा संसाधनों की पहुँच नहीं है, जिससे छात्र आधुनिक शिक्षण तकनीकों का लाभ नहीं उठा पाते। कोविड-19 महामारी के दौरान यह समस्या और अधिक उजागर हुई, जब ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

निष्कर्ष:

सोनीपत जिला, जो 22 दिसम्बर 1972 को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित हुआ, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हरित क्रांति के दौर से लेकर आज के औद्योगिक एवं शैक्षणिक विकास तक, इस जिले ने निरंतर प्रगति की है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल जनसंख्या 14,50,001 थी, जिसमें लगभग 69 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण विकास इस जिले की पहचान रहा है, जिसमें सड़क, परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा और कौशल विकास प्रमुख आधार हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी योजनाओं ने ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया है। शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। पुरुष साक्षरता 87.2 प्रतिशत है, जबकि महिला साक्षरता 69.8 प्रतिशत पर सीमित है, जो सामाजिक असमानता को दर्शाता है। यही नहीं, डिजिटल डिवाइड और उच्चतर शिक्षा में असमान अवसर भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। सड़क और परिवहन नेटवर्क के

विस्तार से कृषि उत्पादन का विपणन आसान हुआ है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन स्तर को सुधारने में योगदान दिया है। समग्र रूप से कहा जाए तो, सोनीपत में ग्रामीण सुविधाओं की स्थिति निरंतर सुधार की ओर अग्रसर है। यद्यपि शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी सरकारी योजनाओं और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से यह जिला ग्रामीण विकास का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।

सन्दर्भ:

1. भारत सरकार. (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका: सोनीपत, हरियाणा*. जनगणना संचालन निदेशालय, हरियाणा.
2. सिंह, आर. एवं कुमार, अ. (2020). हरियाणा में कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन और शहरीकरण: सोनीपत जिले का अध्ययन. *भारतीय भूगोल जर्नल*, 22(2), 55–68.
3. यादव, ए. एवं कौर, म. (2018). सोनीपत जिले में जनसांख्यिकी और शहरीकरण प्रवृत्तियाँ. *भारतीय क्षेत्रीय अध्ययन जर्नल*, 50(1), 33–45.
4. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. (2019). *जिलावार मिट्टी उर्वरता रिपोर्ट: हरियाणा*. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग.
5. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग. (2020). *हरियाणा की जलवायु: सोनीपत जिले की वार्षिक जलवायु रिपोर्ट*. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार.
6. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, हरियाणा सरकार. (2021). *आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21: जिला प्रोफाइल सोनीपत*. हरियाणा सरकार.
7. कुमार, स. (2017). उद्योगीकरण द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास: सोनीपत जिले का एक अध्ययन. *इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल वीकली*, 52(14), 78–84.
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI). (2023). *वार्षिक रिपोर्ट 2022–23: NH-44 का विकास एवं सोनीपत जिले पर आर्थिक प्रभाव*. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार.
9. उत्तरी रेलवे. (2021). *रेलवे कनेक्टिविटी एवं हरियाणा का आर्थिक विकास: सोनीपत जिले पर केंद्रित रिपोर्ट*. रेल मंत्रालय, भारत सरकार.
10. शर्मा, न. एवं गुप्ता, प. (2020). सोनीपत जिले में भूजल संसाधनों और जल प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन. *अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान जर्नल*, 10(2), 112–120.
11. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB). (2021). *हरियाणा पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021: सोनीपत जिला*. हरियाणा सरकार.